

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. House is adjourning now.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Now there are so many things to be spoken about.

Sir, we have done a lot of progress in the atomic energy field. We have done a lot of progress in space research. We have done a lot of progress in science and technology. But we have to do a lot in the field of transport, railways, national highways, all these things.

Last point, Sir, I would like to conclude because I do not want to speak much because my colleague, Smt. Suryakanta Patil is going to raise very pertinent issues of our region. I have left everything to her because we come from the same place.

We would like to build this country. I want to conclude my speech with a quotation from Madam Gandhi's speech:

"We would like to build this country in such a manner that if India's name is mentioned anywhere or if its citizens go anywhere, there goes with them a new life, a new strength and a new ideology."

This is what we want this country to be.

With these few lines I conclude my speech.

The House adjourned for lunch at thirtyone minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock. [The Vice-Chairman (Shrimati Kanak Mukherjee) in the Chair].

RE. STATEMENT ON ARTICLE 249

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam, I have to take one minute. We would like to be informed when the statement on Article 249 is likely to be made. The hon. Minister for Parliamentary Affairs is here and he can inform the House. We were given to understand that it would be made at 2.30 p.m. and were informed that a meeting is taking place between the Attorney-General and the Home Minister. We just want to know when that statement is likely to be made.

संहदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : जैसा आपको मालूम है, अपोजीशन के साथ बातचीत हो रही है। अभी तो एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस चल रही है। उसके बाद बता देने।

श्री जसवन्त सिंह (राजस्थान) : कुछ समय का अन्दाजा बता दीजिये।

श्री सीता राम केसरी : अभी तो बातचीत चल रही है, समय का अन्दाजा क्या बताएँ। आपके दल के नेता वहां पर हैं। आपने यहां पर यह प्रश्न उठा दिया?

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1986—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI KANAK MUKHERJEE): Now we will take up further discussion on the Appropriation (No. 4) Bill, 1986. Shrimati Surya Kanta J. Patil.

श्रीमती सूर्यकांता जयवन्तराव पाटील : (महाराष्ट्र): माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में पहली बार बोलने जा रही हूं। आपने यह जो मौका मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूं।

वित्त मंत्री जी ने जो यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप अपनी भलमन्साहत के लिए सारे

[श्रोमनों सूर्योऽता जयवन्तराव पाटोल] देश में प्रसिद्ध हैं। उस बात का आदर रखते हुए कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। बहुत से विभाग हैं जिन पर धन खर्च होना है। बहुत से विभागों पर जो धन वितरित किया गया है उस वितरण व्यवस्था पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन चन्द बातें हैं जिन बातों से साधे इस देश के गरीब आदमी का संबंध पड़ता है, जो इस देश का सही मायनों में हिस्सेदार है। उस गरीब किसान का जिन बातों से संबंध है, जिन नौतियों से संबंध है, उन नौतियों पर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बाटर रिसलेज पर आपने जो 239 करोड़ रुपये की राशि रखी है, यह मेरी समझ में बहुत कम नजर आता है। नेचुरल कैलामिटाज पर जो आपने 400 करोड़ रुपये रखे हैं—नेचुरल कैलामिटेज इस देश के जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। आप दिन सुधा पड़ता है, आप दिन तूफान उठते हैं, कुछ न कुछ इस देश में घटता है। रहता है और लौट नेचुरल कैलामिटाज होता है। इनमें कुछ हमारे द्वारा पैदा की हुई कैलामिटेज भी होते हैं। इसलिए जो आपने 4 सौ करोड़ रुपये रखे हैं वह मुझे काफी कम नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं भी महोदय इस पर जरूर ध्यान देंगे ऐसे मुझे पूरा उम्मद है।

माननाय वित्त मंत्री जी का मैं एक बात के लिये बहुत लहरे दिल से अभिनन्दन करना चाहती हूँ, उनको प्रधन्यवाद देता चाहती हूँ जो उन्होंने नारकोटिक कन्ट्रोल व्यूरो के स्थापना के। नारकोटिक कन्ट्रोल इस देश में बहुत ध्हले ही जाना चाहिए था, इसको बहुत ध्हले से वह द्यावश्यकता था। इस देश के नवा पड़ को ध्वस्त करने के लिये बाहर याकियां जो साजिश कर रहे हैं उस साजिश को हमने अभी तक नजर अंदाज किया है। लेकिन देर आधद द्वारस्त आथद अब भंवी महोदय ने जो नारकोटिक कन्ट्रोल व्यूरो की बात कही

है इसके लिये मैं सारे देशवासियों का तरफ से, सारे युवा पीढ़ी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, अब मैं आपने मूल विषय की तरफ आना चाहती हूँ। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह सारे बात धनराजि के विवरण के सम्बंध में है। धनराजि के विवरण के विवरण को देखने के पश्चात हमारे दिल में एक कसक है, दुख है और उस दुख का ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहत हूँ कि वह दुख क्या है। मैं हिन्दुस्तान के उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो आदम इस देश का किसान है। इस देश का 90 प्रतिशत आजादी खेती करने वाले खेतिहारों की है। खुश किस्मती तब होती जब हिन्दुस्तान का किसान प्रमुख उद्योजक कहलाता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 90 प्रतिशत हिस्से में रहने वाला यह किसान मजदूर कहलाता है, उद्योजक नहीं। क्योंकि खेतिहारों का, एग्रीकल्चर को हमने उद्योगों का दर्जा नहीं दिया है। आजादी के 35 साल बाद भी इस देश का जो किसान है वह मजदूर कहलाता है, मालिक नहीं, उद्योजक नहीं, कारखानेदार नहीं जबकि इस देश को खेता को इस देश के एग्री-कल्चर को इस देश का प्रमुख उद्योग होना चाहिए। इस तरफ अगर आप कुछ कर सकें तो आपको जरूर करना चाहिए। देश के इस सर्वोच्च सभागृह में किसानों की तरफ, उनके पक्ष में काफी बोला जाता है और काफी कुछ किया भी गया है। हम यह नहीं कहते कि सरकार ने कुछ किया हाँ नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ किया है और देश को हमने काफी आगे लाया है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर से उस किसान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि किसानों की क्या स्थिति है। एक किसान अपनी फसल उगाता है और 10-11 भाफी मेहनत करने के

बाद, मैं उस छोटे किसान को बात कहने जा रही हूँ, जिनके खेतों में इरीगेशन नहीं है और अत्यल्प जमीन के मालिक हैं, जिनके खेतों में नहरें नहीं हैं 'केनाल' नहीं है, उन किसानों की बात मैं कह रही हूँ। 10 महीने बुवाई के बाद वह हमेशा आसमान की तरफ देखता है कि कब आसमान बरसेगा और कब उसकी जमीन हरीभरी होगी और कब वह अपनी फसल ले जा सकेगा। 10 महीने की मेहनत के बाद फसल कटने को आती है और तब उसकी दीवाली आती है। श्रीमन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस महीने के बाद भी, दीवाली का मतलब होता है अंधेरा कम होना। लाखों दीप सीमेंट के जंगलों में जलते हैं लेकिन हमारे इन बेचारे किसानों के जो घर में दीप जलता है उसको जलाने के लिये, उसे तेल नहीं मिलता। मैं उस तेल की हमें फिर है। करोड़ों लोगों को खिलाने वाला वह किसान अपने घर को खिलाने के काबिल नहीं रह गया है। हमारी प्लानिंग शायद कुछ अन्यथा कर रही है ऐसा अगर किसान होने के नाते हमारे दिल में शक पैदा हो तो शायद आप लोग हमें क्षमा करेंगे इस बात पर। हमारे देहात में हमारा किसान तो दीवाली क। दीप जलाने से डर रहा है, हिसाब-किताब लगा रहा है कि उसकी आर्थिक अवस्था इतनी क्षीण अवस्था प्राप्त कर चुकी है कि अपनी निजी रोजमरा की जहरतें पूरी नहीं कर पाता है। मुझे कार्ल मार्क्स की बात याद आती है। कार्ल मार्क्स को मैंने थोड़ा पढ़ा है और थोड़ा समझने की कोशिश की है। मैं शायद कुछ ज्यादा तो नहीं समझ पायी हूँ लेकिन कार्ल मार्क्स ने कुछ ठीक कहा है, एप्रीकल्चर के बारे में, पूँजीवाद के बारे में समाजवाद के बारे में। "किसी भी देश में पूँजीवाद का जब विकास होने लगता है तो वहाँ के खेतिहार लोगों को दबा कर ही यह विकास की क्रिया पूरी होती है यानी पूँजीवाद मजबूत तथा शक्तिशाली होती है।" यह बात कितने बड़े पैमाने पर सच है इस बात का मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही माहौल मुझे नजर आ रहा है।

श्रीमन, आप थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें। आपका तबज्जो की मैं आशा करती हूँ। आज मैं मार्क्स की बात को थोड़ा कुछ अधिक ठीक रूप से कह रही हूँ। मुझे याद आता है, महात्मा गांधी जी की जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए संसद में गोलियाँ झेलीं और उनके दिल में शायद वह एक सपना था जो उनके साथ दफन हुआ। ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ। उसको पूरा करने के लिए काफी कोशिश भी हमने जरूर की है लेकिन आजादी की लड़ाई के समय उन्होंने दो बातों के ऊपर प्राथमिकता दी था। ग्रामीण विकास, ग्रामीण स्वराज तथा इषि विकास पर। आजादी के बाद हिन्दुस्तान का भविष्य ग्रामीण विकास पर निर्भर होगा, ऐसी उनकी विचार-धारा थी लेकिन अफसोस आज हम उससे कुछ थोड़ा सा हटे हुए नजर आते हैं। आजादी के बाद देहात खाली होते गये। गांवों से लोग शहरों की ओर आगे लगे रोजी-रोटी के लिए। गांधी जी ने कहा था ग्रामों की ओर चलो देहात की ओर चलो और हमारे देहात के किसान भाई देहात के मजदूर भाई सीमेंट के उन जंगलों की ओर आगे लगे। श्रीमन, सीमेंट के जंगलों में उनको घर तो नहीं नहीं हुए फटपाथ पर झगड़ा-झगड़ा उन्होंने बना ली और अपने जिन्दगी का रास्ता बाटना तय कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा आपको लगता है, क्या आगे बढ़ी सोचा है कि उन्होंने यह मजबूरी क्यों स्वीकार की? क्यों उन्होंने अपने घर और खेत को छोड़कर सीमेंट के जंगलों में रहना पसंद किया कि है-कि कि तरह क्या उनके आगे जिन्दगी के जरूरी बांधिवार नहीं था, क्या हम उनके अपना अधिवार दे नहीं पाए। क्या इस पर आप सोचेंगे? इस बात पर संतुलने के लिए मजबूर होना बहुत उत्तर लगता है। इस पर आप जरूर गौर वर्णे। हमारे ग्रामीण भाई, बम्बई, कलापत्ता, मद्रास, दिल्ली के शहरों में फटपाथों पर ज़दून बिता रहे हैं। शहरों में हमारा विस्तार या मजबूर कोई भी अभिर आट्मा नहीं बना रहा या तो मिल में मजदूरी करता है या सुवह दस

[श्रीमती सूर्यकांता जगदन्तराव पाटोल]

से पांच बजे तक काम करने वाला बाहु है। तेहत मुने हो गये ऐसा क्यों हुआ? उक्त देशों और बैधर किस तो का भै प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए भै चुनीतों के साथ इस सदन में कहना चाहतो है। इस सरकार से आपके माइट्रम से कि इस बात के लिए कार्य-विधान दोषा है। भै आपके माइट्रम से ग्रामोण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से कहना चाहतो है कि आपका व्याय समान नहीं है शायद इस देश में। कियान एह ऐसा व्यक्ति है जो अपने खून पसने से बनाई हुई बस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। बाल्क उसे जो मिलता है वह निर्धारित रखते बल्कि उसने लोक खेतों करते हैं, यह सोचते को बात है। अब हमनारो कर्मस को बात को ही लाजिये। जित महाराष्ट्र का भै प्रतिनिधित्व करते हैं उन महाराष्ट्र को कर्मस की बात भै कहने जा रही है। कपड़े के दाम सरकार रोक नहीं सकती है। आज घटिया से घटिया करड़ा 10-15 रुपये प्रति मोटर के हिंगाव से बिना है लेकिन हमारे कियान भाई 21वीं सदी में जाते हुए भी वहीं के वहीं हैं। इसलिए भै आपके माइट्रम से शासन से नियंत्रित करना चाहतो है कि ग्रामोण विकास से इस देश का विकास है। अत्मा है, उसको जो वित रखने के लिए आपको कियान के खेतों में पैदा होने वाला चाजों का दाम उत्पादन खर्च पर अधारित देना होगा। जब तक सरकार इस बात को प्राथमिकता नहीं देगी तब तक हम अपने देश को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। हम हिन्दुस्तान को अर्थ-व्यवस्था का निर्माण पूरोह की नकल करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरोह का सारा विकास वहीं की सारी अर्थ-व्यवस्था कम्पटराइजेशन तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निर्भर है। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को बुनियाद है कृषि और उस पर अवश्यकता उद्योग। वाकी सारे उद्योग दूसरा स्थान रखते हैं। हर चीज का अपना महाराष्ट्र है जैसे थालों में रोटी के साथ और भी पुराने पदार्थ हैं लेकिन रोटी के बांगर खाली दाल सब्जो नहीं

खा सकते, अचार नहीं खा सकते हैं, ठोक उसी तरह से हिन्दुस्तान को कृषि विकास के सिवाय कैसे रख सकते हैं। बाढ़ और सूखा तो लगा है कि ग्रामोणों के लिए खगास ग्रहण है। इस बा और सूखे पर करोड़ों रुपये बाहे होते हैं। उपका हिंडब उसी माने में लगाया जाये तो पता चलेगा कि अनाज की जगह पौधाफिस खुबों से चढ़ाया जाता है। बा और सूखे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारी नयों तकनीक हम किन लोगों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं? जो शहरों की चारदोलारी में सुरक्षत जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए और उन 70 प्रतिशत लोगों का बा होगा जो आपकी ओर देख रहे हैं और आस लगाये हुए हैं। आप शहरों के रुख को ग्रामों की तरफ मोड़ दोजिए। महात्मा गांधी का सपना सच हो जायेगा। उठाइये बड़े-बड़े कारखानों को शहरों से, उनका तब तक ल हसेंस रिन्यू मर्कोजिए जब तक वे पिछड़े हुए ग्रामोण भागों में अपने कारखाने न लगायें। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको ट्रांपोर्ट की सुविधा देना होगा और बहुत सी बातों को सोचना होगा। आपको प्लानिंग के अन्दर काफी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी और वे तब्दीलियां शायद बेसिक होंगी। वे बेसिक तब्दीलियां लाने के लिए सोना भी बहुत बड़ा और जर्वर्डस्त चाहिए, सोने में चाहिए चाहूत, दर्द और दर्द की समझने की तरफ तथा आदत भी होनी चाहिए किसी के दुख को समझने की, इसके इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। जो करोड़ों रुपया बाढ़ और सूखे पर व्यय होता है तो निर्धारित कोजिए कि इस देश के सात लाख गांवों में पक्की सड़कें बनायी जायेंगी, जहां ब्राड गेज की आवश्यकता है वहीं वह आवश्यक प्राथमिकता के साथ बनाई जायेगी। मैं जिस विभाग से संबंधित हूं, महोदया, वहां पिछले 32 साल से हमारी एक ही मांग है। हम मराठवाड़ा विभाग के लोग 1948 में बिना शर्त महाराष्ट्र में शामिल हुए थे। हम लोग आलोड़ निजाम स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि क्या हमने गलती की शर्त

न रखकर। लेकिन नहीं हम देश को आजादी के साथ-साथ देश को एक साथ भी रखना चाहते हैं उसके लिए हमने चाहे जो त्याग किया होगा और आगे भी जो करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके माने यह यह नहीं होता कि कोई समझदार बच्चा अपने घर की गरिबों को समझता है तो उसको हमेशा के लिए भूखा रखा जाये। सही मान वह होता है जो धर में जो भी रुखा सूखा होता है उसको समान बांटती है, अपने हर बच्चे को उतना ही देती है। जितना एक बच्चे को मिलेगा उतना ही दूसरे बच्चे को भी मिलेगा। यह नहीं कि मरठवड़ा के बच्चे समझदार हैं तो उनको हम हमेशा के लिए भूखा रखें, उनकी तरफ न देखें और उनसे यह कहा जाता रहे कि हमारे पास पैसा कम है। हम कब तक सुनेंगे? पैसा नहीं है, हमारे विभाग को पैसा नहीं मिल रहा है? लेकिन 70-80 करोड़ की आबादी को देखते हुए हमें तो सच नहीं लगता है। आपके हर विभाग में धाटा चल रहा है, इसके माने कि हमारी जो वेसिक मांग हैं, जो वेसिक अधिकार हैं उनसे आप हमको वंचित रखेंगे? क्या हमको वह अधिकार नहीं देंगे जो वेसिकलों हमको मिलन: च.हिए जो कास्टीट्यूशनलों हमको मिलन: चाहिए। बहुत ज्यादा गहरे बात न करते हुए मैं खाली हमारी ब्राड गेज की मांग को ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वह मांग आज की नहीं है। वित्त मंत्री जो से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आज तो नहीं लेकिन आने वाले विन्टर सेशन में जो पूरक मांग होंगी, सप्लामेंटरी डिमांड्स होंगी। आप उसमें हमारी इस तकलीफ के ऊपर जो हम 32 सालों से कह रहे हैं, उन पर गौर करभाइयेगा। मरठवड़ा जो एक पिछड़ा विभाग है उसमें ब्राड गेज हमें शान्त-शांकत के लिए नहीं लेकिन विकास का साधन मानकर चाहिए। वहाँ जब तक ब्राड गेज की सुविधा नहीं देंगे तब तक कोई भी उद्योग उस पिछड़े हुए विभाग में नहीं आयेगा और हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। इन सौ बोमारियों का एक ही इलाज है, एक ही दवा है कि आप इस देश की आत्मा को जीवित कीजिए, बलशावी

कीजिए तब यह हिन्दुस्तान वह हिन्दुस्तान बन जायेगा जहाँ से कभी सोने का धर्मा निकलता था। यह वही धरती है जो आज भी हिन्दुस्तान में सोना उगाती है, जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया। इस देश के किसानों ने देश की ज्ञानी पटने तक अनाजों से भरी है। खेद है मुझे कि वह किसान अभी भी भिखारी बना दर-दर भटक रहा है। हिन्दुस्तान की आत्मा भटक रही है। उस आत्मा की आबादी को प्यार से, प्रेम से, सौहार्द से सुनना होगा उनकी मैनहनत को सही नाप से तौलना होगा चाहे वह कपास हो, भूंगफली हो, चावल हो, गन्ना हो, कोई भी चोज हो उसका सही निर्धारित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है उत्पादन और उत्पादकता। इस बातों की बाजीयाद हैं वह करोड़ों किसान, मजदूर जौं देहातों में रहते हैं। यही सब हमारे बीस-सूती कार्य क्रम के अन्तर्गत हैं, लेकिन उन बीस-सूती कार्यक्रमों का संचालन करने वाले साहिबान का उन किसानों से तथा गरीबों से कोई वास्तव नहीं है। यह कार्यक्रम ठांक नहीं चल पा रहा है क्योंकि जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है, वह उस कार्यक्रम का बोरिया-विस्तर लपेट देना चाहते हैं, वह चाहते ही नहीं कि इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मजदूर आदमी, इस देश का किसान आदमी इस बीस-सूती गीता के माध्यम से आगे जाए।

समाजवाद के विरोधी तो हमेशा से रहे हैं। महोदया, समाजवाद को क्यों नहीं हम पुरी तरह से ला पा रहे हैं जब कि समाजवाद की बात तो महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, हमारी आदरणीया मोहतरमा इन्दिरा जी से लेकर हमारे युवा नेता राजीव जी तक वह बात चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, मैं इस बात को जहर धान में रखती हूं। मुझे मालूम है कि जब-जब समाजवाद को लाने की कोशिश की गई, तब-तब समाजवाद के आड़े में जो लोग आते हैं वह किन लोगों के बीच में फैल कर बैठे हुए हैं, उनका कितना भासी गठन है? उस गठन को हमें तोड़ना होगा।

[श्रीमतीं सूर्यकांता जयवन्तराव पाटिल]

सालों से, वर्षों से कोशिश की जा रही है। समाजवाद के घातक शत्रु कैन हैं, उन शत्रुओं को ढूँढ़ना होगा। अगर वह शत्रु हमारे बीच में भी मिलते हैं, वह कहीं भी मिलते हैं, वह चाहे हमारे कितने प्रियजन क्यों न हों, उन शत्रुओं को खत्म करना होगा। तभी तो हम समाजवाद की ओर जा सकेंगे, महोदया। लेकिन बदकिस्मती से हर समय समाजवाद के दुश्मनों की ताकत अधिक लगती है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर छड़े दिखाई देते हैं।

हमारे हर नेता ने पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देने की बात की है, लेकिन हम पब्लिक सैक्टर में पीछे हो रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर हम से आगे जा रहा है। क्यों पब्लिक सैक्टर के हम पीछे पड़ रहे हैं, कभी विचार किया है? पब्लिक सैक्टर वा हर उद्योग क्यों ऐसा हो रहा है कि उसमें हमें घाटा ही घाटा मिल रहा है? उस घाटे की तरफ हम कभी देखते नहीं हैं। जब जब बात आती है कि किसानों की, तब हम कहते हैं कि इस देश का पब्लिक सैक्टर का उद्योग घाटे में चल रहा है। इसलिए हम पूरा पैसा, पूरी पूँजी जुटा नहीं पाते हैं और उसकी वजह से हम आपको न्याय नहीं दे पाते हैं। यह ग्रक्षम्य-सा मुझे लगता है।

आजादी के 35 साल के बाद की शोही जो 38 साल की होकर आपके सामने पुकार रही है कि यह अन्याय है, यह न्याय नहीं है इस देश के किसानों के प्रति, जो इस देश का सही मायनों में मालिक है। इसलिए हम आपसे यह गजारिश करती हैं, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हैं कि आप किसानों को कुछ मूल्य जो दे रहे हैं, वह आपको खर्च के ऊपर आधारित देने होंगे, देहातों का सुधार करना होगा, देहातों की जो प्राथमिक आवश्यकता है, उसको पूरा कीजिये जैसे बिजली, पानी और शिक्षा। किसानों को कर्जे में छुड़ाने के बजाए उसको मदद कुछ बस्तु के रूप में दी जाए। इसमें पैसे का दुर्घटयोग नहीं होगा, हम यह नहीं बहते

कि किसान पैसे का दुर्घटयोग नहीं बहता है। किसान तो अनपढ़ होते हैं, महोदया, जो सिर्फ बोले और उपजाने वा ध्यान रखते हैं, उनको पैसे के द्विसाव-विताव से कोई मतलब नहीं होता। वह गलतियां कर सकता है, जरूर गलतियां करते हैं।

आपकी जो मदद है, वह पैसे के रूप में उनको न दें, उनको कुएं खोट बर दें, आधुनिक औजार लेकर दें, उनको सस्ते फटिलाईजर उपलब्ध करके दें, तो शायद आपके पैसे का कुछ वह लोग उपयोग कर पायेंगे।

मैं जाते-जाते किसानों की बात के बाद जिस राज्य का है प्रतिनिधित्व करती हूँ, उस महाराष्ट्र की चंद मसायल के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, महोदया।

उपर्युक्तम् (श्रीमती कनक मुखर्जी) : अब बस कीजिए।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटिल : हमारे कुछ मसायल केन्द्रीय सरकार के पास पैदिंग हैं। जल अनुसंधान आयोग-- मेरा निवेदन है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, 25 बड़े तथा 48 मोडिंग्स प्रोजेक्ट्स जो केन्द्रीय शासन भें केन्द्रीय जल आयोग की मान्यता के लिए 1974 से आज 1986 तक इतने पैमाने पर पैदिंग पड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि 1974 से आया हुआ प्रोजेक्ट अगर वह एक लाख का प्रोजेक्ट होगा, तो आज एक करोड़ का बन गया होगा।

हमारी प्लानिंग वाहां से कहां जा रही है? अगर हम किसी प्रोजेक्ट को इतने दिनों पैदिंग रखते हैं मान्यता के लिए, तो हम खुद घाटे में जाते हैं, किसान तो बाद में घाटे में जाएगा। वह तो दौदा ही घाटे में जाने के लिए हुआ है। उसकी जिदगी ही मरने के लिए है, तो हमने उनको प्रदान की है। लेकिन हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो हम पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं,

हमको अगर सही मायनों में आगे बढ़ना है तो ये प्रोजैक्ट्स आपको मंजर करने होंगे। काटन मोनोपली हमारा सब से बड़ा प्रश्न है। काटन की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदावार है, और जहां से हमारे कई माननीय सदस्य भी इस सदन में बैठे हुए हैं, मैं काटन मोनोपली की बात करना चाहती हूं। महोदया, यह घाटे में जा रही है। 350 करोड़ रुपये का घाटा इस काटन मोनोपली को हुआ है। वह घाटा क्यों हुआ है? उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, काटन मोनोपली के जरिए जो कपास की खरीदारी होती है और उसके अन्दर से जो केन्द्र का हिस्सा है वह सी०सी०आई० को खरीदना चाहिए। लेकिन यह सी०सी०आई० वह खरीदती नहीं है। अगर उसने 1/3 हिस्सा खरीद लिया तो हमारी काटन मोनोपली कभी भी घाटे में नहीं जायेगी और इससे केन्द्र शासन को हमारे महाराष्ट्र के किसानों के साथ वफादारी करने का मौका मिलेगा। काटन मोनोपली को जीवित रखना आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। जो सी०सी०आई० के मार्फत काटन की खरीदारी है जो आपका हिस्सा है उसको खरीदने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। मैं अपने राज्य की तरफ से आपको विनती करना चाहती हूं। काटन की ही क्यों सारे अनाज की सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए मैं आपको कहती हूं। जब कपास की पैदावार हो जाती है तब काटन प्राइस तय करने वाले लोग जागते हैं और सोचते हैं कि कोई न कोई प्राइस डिलेयर करनी चाहिए। जब लेट प्राइस डिलेयर होनी शुरू हो जाती है तब हमारा गरीब किसान पैसे के धोखे में आकर सेठ साहूकारों को अपना अनाज और अपनी पैदावार बेचनी शुरू कर देता है। अगर हम प्राइस डिलेयर लेट नहीं करें तो हमारे देश का किसान खुशहाल नजर आयेगा।

महोदया, एक आखिरी हिस्सा है मेरी मांग का और वह रेलवे लाइनों के बारे में है। इसके बारे में हमारे सीनियर सदस्य जाधव जी ने तो कहा ही है, मैं भी उन रेल लाइनों का जिक्र

करना चाहती हूं। ब्राडगेज की लाइनों के लिए हम पिछले तीस साल से मांग कर रहे हैं। मनमाड-औरंगाबाद परली वैजनाथ मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलने के लिए, परमणी पुण्यमुद्घेड़, मिरजलातूर नैरोगेज टू ब्राडगेज और अहमदनगर-बीड़-परली बैंजनाथ नई ब्राडगेज रेलवे लाइन। इन सभी रेलवे लाइनों को आप अगर आने वाली सप्लीमेंट्री डिमांडज के अन्दर रखें तो हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को और सारे सदन को देश के किसानों की ओर कहना चाहती हूं। जैसा मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि इस देश का किसान सही हकदार है, सही हिस्सेदार है और सही मालिक है, लेकिन आज वह फृप्तपाथों में, झांपड़ों में, मिलों में मजदूर के तौर पर दिखाई देता है और फटेहाल में जीता है। हम यह नहीं कहते कि इस देश की बढ़ती हुई तकनीकी से किसानों को कुछ फायदा नहीं होगा। हम शहर विरोधी भी नहीं हैं। हम खुशहाल शहरी भाइयों को देखकर खुशी जरूर मानते हैं, लेकिन भूखे पेट से कितनी खुशहाली व्यक्त की जा सकती है? खुद भूखे रह कर दूसरों की थालियों को गिनना बहुत कठिन बात है, बहुत टेढ़ी बात है। हमारा खुद का अपना पेट भरा हो और हम अपने भाइयों की थालियों में डोसा देखें, किसी की थाली में विश्वानी देखें और हमारी थाली में कुछ भी न हो तो यह कुछ थोड़ा सा गलत लगता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शायद वह किसानों के लिए ही कहा होगा। मैं शेर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, और है :

“मयस्सर नहीं थी जिनकी नजर,
वो खास आम हो गए हैं आज।
जवाहरात से बेश-कीमती थे,
कितने कम दाम हो गए हैं आज।”

और इन शब्दों के साथ अनुपरक मांगों का मैं समर्थन करते हुए अपने दो शब्द पूरे करती हूं।

धन्यवाद।

3.00 P.M.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Let us congratulate her for her very eloquent maiden speech. I am only wondering why maiden speeches argue against the Government but support them. That they should explain.

श्री बॉ. सत्यनारायण रेडी (आंध्र प्रदेश) : मैडम वाइस चेयरमेन जो एप्रोप्रियेशन विल हमारे सामने हैं, इसमें 1318,40,40,000 का टोटल आउट-लेज बताया गया है। लेकिन जो अहम समस्याएं हमारे देश के सामने हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जिन डिपार्टमेंट्स के लिए जो रकम एप्रोप्रियेशन विल में बताई गई है, वह बहुत ही नाकामी है।

[उपसभापति भवोदय पाठार्सन हुए।]

महोदय, जो अहम चीजें हमारी हैं, वह हैं—एरोगेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, रुरल डेवलपमेंट, प्रोबोजन फार डिक्षित वाटर, नेशनल हाइवे, न्यू रेलवे लाइन, रेमूनरेटिव प्राइसेज फार फारमर्स। यह चीजें देश को शक्तिशाली, देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी हैं और इन तमाम चीजों के लिए काफी रकम रखनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर कोई ज्यादा गुंजाइश इन चीजों के लिए नहीं है ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, you may continue tomorrow. We are now taking up the Resolution. Now Mr. Buta Singh to move the statutory resolution.

STATUTORY RESOLUTION IN PURSUANCE OF ARTICLE 249 OF THE CONSTITUTION

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Sir, I beg to move the following Resolution:

That this House do resolve, in pursuance of Article 249 of the Constitution, that it is necessary in the national interest that Parliament should, for a period of one year from 12th August, 1986, make laws with respect to the following matters, namely:—

Public Order (but not including the use of any naval, military or air force or any other armed force of the Union or of any other force subject to the control of the Union or of any contingent or unit thereof in aid of the civil power) (Entry I of List II—State List.);

Police (including railway and village police) subject to the provisions of entry 2A of List I (Entry 2 of List II—State List.);

Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein, arrangements with other States for the use of prisons and other institutions (Entry 4 of List II—State List.);

Offences against laws with respect to any of the matters in this List (Entry 64 of List II—State List.);

Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List (Entry 65 of List II—State List.);

Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court (Entry 66 of List II—State List.).

Sir, in the context of the anti-national secessionist and terrorist activities in some parts of the country, concern has been expressed in this House as also outside about the threat posed to the stability, unity and integrity of India and the need to take effective steps to meet the situation. There are also reports about assistance being